सरकार काले धन की उत्पत्ति, वृद्धि और उसके उपयोग को रोकने के लिए, समय-समय पर उपयुक्त समझे जाने वाले आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपाय कर रही है । इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) योजनाबद्ध सर्वेक्षण कार्रवाइयां ।

(ii) उपयुक्त मामलों में तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाइयां ।

(iii) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना की जांच-पड़ताल करना ।

(iv) नियंत्रणीय चुनिन्दा मामलों में गहन जांच करना ।

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

1670. श्री शरद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा 1984 से प्रति-वर्ष किस-किस वित्तीय संस्था से कितने-कितने ऋण कितनी-कितनी ब्याज दर पर लिए गए हैं ;

(ख) अगस्त, 1988 तक भारत पर कुल कितने रुपये का विदेशी कर्ज हो चुका है ;

(ग) 1984 से अब तक कितने रुपये के कर्जे का भुगतान किया जा चुका है ; और

(घ) 1984 से अब तक ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवार्डो फलेरियो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट 148, अनुपत्र संख्या 77]**

Convening of an all-party meeting on Punjab problem

1671. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, convened an all party meeting to find out a solution to the Punjab problem; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Prime Minister visited Punjab on 21-9-1988 and announced that an all party meeting to discuss the Punjab problem would be held. A Cabinet Sub-Committee has since been constituted to work out details of the agenda for the meeting.

Setting up of an export monitoring cell at Hyderabad

1672. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an Export Monitoring Cell at Hyderabad; and

(b) if so, what functions are proposed to be assigned to this Cell?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) While Government is keen to involve State Governments in exports, no specific scheme has yet been formulated to set up an Export Monitoring Cell in different States.